



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2003/भाद्र 10, 1925

No. 215]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2003/BHADRA 10, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2003

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेप्स के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच-अंतिम निष्कर्ष।

सं. 14/31/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेजरिंग टेप्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में 31.1.2003 की अधिसूचना के द्वारा प्रारंभिक जांच-परिणामों को अधिसूचित किया तथा हितबद्ध पार्टियों से प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों, यदि कोई हों, से अवगत कराने का अनुरोध किया:

- (ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति अग्रेषित की और उन्हें उक्त परिणामों पर अपने विचार, यदि कोई हों, पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया।
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास/उच्चायोगों/प्रतिनिध को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार भेजें :
- (iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक रूप से 1 मई, 2003 को सुनने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें घरेलू उद्योग, उपभोक्ता उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन निष्कर्षों पर हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर विचार किया:
- (v) प्राधिकारी ने अनुरोध पर सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी :
- (vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, का संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है। परन्तु हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में विचार किया गया है:
- (vii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया :
- (viii) जांच अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2002 तक : है।

- (ix) इस अधिसूचना में *** से हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है :

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु :

मै9 सुदेश एंटरप्राइजेज के विचार

2.. प्रारंभिक जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद को मेजरिंग टेप्स तथा हिस्सों और पुर्जों के रूप में परिभाषित किया गया है। हिस्सों या संघटकों का पता लगाने अथवा नामों को देने के बारे में न तो प्रारंभिक निष्कर्षों में और न ही याचिका में परवाह की गई है जिन्हें इन निष्कर्षों में शामिल किए जाने की मांग की है। अनुरोध किया जाता है कि इस्पात की छड़े कुछेक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही मेजरिंग टेप के संघटक हिस्से की विशिष्टियां अर्जित करती हैं। हिस्सों तथा संघटकों के उनके आयातों की मात्रा के अभिज्ञान के अभाव में ऐसे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इन पुर्जों का आयात पाटित कीमतों पर हुआ है अथवा उन्होंने याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाई है।

3. प्रारंभिक जांच निष्कर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य मूल्य का परिकलन केवल इस्पात टेपों तथा फाइबर ग्लास टेपों के लिए ही किया गया है, तथापि सामान्य मूल्य का परिकलन हिस्सों/संघटकों के लिए नहीं किया गया है। इसी प्रकार से निर्यात कीमत केवल टेपों के लिए है न कि हिस्सों-पुर्जों के लिए।

4. याचिकाकर्ताओं के विचार

मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद मेजरिंग टेप्स है और इसके हिस्से और संघटकक है क्योंकि हिस्सों और संघटकों के आयात मेजरिंग टेपों के आयातों का ही अंग है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेजरिंग टेप और चीन से आयातित मेजरिंग टेप विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं का शुल्क वर्गीकरण आदि जैसी भौतिक तथा रासायनिक विशिष्टियों के संदर्भ में तुलनीय है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

5. विचाराधीन उत्पाद 'मापन फीता' है, इसके भाग और संघटक आदि, इस्पात के सभी प्रकार के मापन और फाइबर ग्लास के फीते और उनके भाग अथवा संघटक मौजूदा याचिका की विषयवस्तु हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई आदि नापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फोरमैन, मिस्त्री, बढ़ई, वानिकी विभागों और दर्जियों आदि द्वारा किया जाता है। मापन फीते टैम्पर किए गए उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील ब्लेड से विनिर्मित होते हैं तथा संक्षारण और जंग से बचाने के लिए विशेष इनेमल से फासफेटेड और लेपित किया जाता है। मापन फीते का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:-

क. अत्यधिक यथार्थमापी व्यावसायिक कार्य :

ख. किसी वस्तु की गहराई, चौड़ाई अथवा लम्बाई नापने के लिए:

ग. संक्षेपण और सर्वेक्षण

6. तकनीकी शब्दों में मापन फीतों को फीते की लम्बाई और चौड़ाई, इसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल स्टील अथवा फाइबर ग्लास और अंततः यथार्थमापन, जिसके लिए आयामों को फीते पर अंकित किया जाता है, के संबंध में परिभाषित किया जाता है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 90 के उपशीर्ष 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि संबद्ध वस्तुएं उपर्युक्त उपशीर्षों के अंतर्गत आयात कीजा रही हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा जांचके क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि जांचमें सभी प्रकार के स्टील मापन और फाइबर ग्लास के फीते तथा उनके भाग और घटक शामिल हैं तथा ये जांच की विषय वस्तु हैं। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के उद्देश्य हेतु केवल किग्रा0 आधार पर उपयुक्त तुलना की है।

7. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा चीन जन0 गण0 से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा चीन जन0 गण0 से आयातित विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। यह दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपयोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा चीन जन० गण० से आयातित संबद्ध मापन फीतों को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए ।

8. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी तथा चीन के विनिर्माताओं की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी की तुलना चीन के विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से की जा सकती है । तथापि प्रत्येक विनिर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी निर्माण प्रक्रिया को उन्नत बनाता है ।

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच में स्टील मेज़रिंग और फाइबर ग्लास टेपों और उनके भागों, घटकों के सभी प्रकार शामिल हैं और ये सभी विचाराधीन सामग्री हैं । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ मात्र कि.ग्रा. आधार पर उचित तुलनाएँ की हैं । प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 2(घ) के अंतर्गत घरेलू उत्पाद द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु समान वस्तु हैं ।

घ. घरेलू उद्योग

मै० सुदेश एंटरप्राइजेज के विचार

10. शुल्क का निवेदन करने वाले सभी याचिकाकर्ता और समर्थकों को बाहर रखा जाना है जबकि मै० स्कनन ने स्वयं जांच अवधि के दौरान टेपों का आयात किया है तथा दूसरों ने चीन से घटकों का आयात किया है । चूंकि टेप और घटक दोनों ही विचाराधीन उत्पाद हैं, अतः कोई घरेलू उद्योग नहीं है और याचिका को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

11. हम यह भी अनुरोध करते हैं कि एक सामान्य पत्र समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मै० स्कनन और मै० क्लास जैसे विनिर्माताओं को अपने उत्पादन, बिक्री, विनिर्माण लागत और आयातों के बारे में संगत सूचना उपलब्ध करा कर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए । ऐसे सहयोग की अनुपस्थिति में मै० स्कनन और मै० क्लास जैसी कंपनियों को प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ।

12. मै0 क्लास को छोड़ दिया जाना चाहिए चूंकि वे मेज़रिंग टेप के विनिर्माता नहीं हैं। वेमात्र गैर-अंशांकित मेज़रिंग टेपों की बिक्री करते हैं जिन पर कोई मार्किंग नहीं होती है। बिना मार्किंग वाले टेप मेज़रिंग टेप नहीं होते चूंकि उन्हें मापन के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

13. प्रारंभिक जांच परिणामों में पैराग्राफ ख(ख) में यह कहा गया है कि कुल घरलू उत्पादन 608343 कि० ग्रा० है और संबद्ध वस्तु के उत्पादन में याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा 90% है। अतः याचिकाकर्ता कंपनियाँ दावा करती हैं कि जांच अवधि के दौरान उनका उत्पादन 547508 कि.ग्रा. था। चूंकि यह उत्पादन जांच अवधि (15 महीने) के लिए निर्देशित है, अतः हम मान लेते हैं कि यथानुपात आधार पर 12 महीनों की अवधि के लिए उत्पादन 438006 कि.ग्रा. होगा। सामान्य तौर पर मेज़रिंग टेप विभिन्न आकार-प्रकार के होते हैं। मेज़रिंग टेप का भार विभिन्न आकारों के लिए अलग-अलग होता है। याचिका में यह कहा गया है कि उत्पादन में अधिकता 3 मीटर की लंबाई वाले पॉकेट मेज़रिंग टेपों की है। 3 मीटर के पॉकेट मेज़रिंग टेप के एक नग का भारत लगभग 100 ग्राम होता है। अतः निर्देशित भारत के आधार पर याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन 43,80,060 नगों का रहा होगा। हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा टेपों की इतनी मात्रा का उत्पादन नहीं किया गया है, चूंकि 2001-02 अवधि के लिए तुलन-पत्र में भार के भुगतान और मापन प्रभारों के आंकड़े इससे काफी कम मात्रा के लिए हैं।

14. भारत एवं मापन मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के साथ पठित भारत एवं मापन मानक अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रत्येक भार या मापन को क्षेत्राधिकार निरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं मुद्रांकित किया जाना होता है। इस अधिनियम के अनुबंध में ऐसे सत्यापनों और मुद्रांकनों को निर्देशित किया गया है। ये प्रभार मेज़रिंग टेप की लंबाई व आकार के आधार पर अलग-अलग होते हैं। पंजाब राज्य के बाहर बिक्री के लिए 3 मीटर लंबाई वाले पॉकेट टेपों पर लागू होनेवाला प्रभार 6.25 रुपये प्रति नग है। दिनांक 13 मार्च, 2002 की अधिसूचना के अनुसार पंजाब राज्य के भीतर की गई बिक्रियों के बारे में 3 मीटर लंबाई वाले पॉकेट प्रकार के प्लास्टिक और स्टील टेपों के मामले में लागू होने वाला प्रभार 5 रू० और उससे अधिक है। वर्ष 2001-2002 के लिए लाभ-हानि तुलन पत्र में मै० फ्रीमैन्स मीज़र लि०, जुगियाना रोड, लुधियाना के मामले में भारत एवं मापन प्रभार 14,34,300 रू० प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ मात्र 2,86,860 नगों की बिक्री है। इसी प्रकार, एफ एम आई लि०, फिरोजपुर रोड, लुधियाना के मामले में भुगतान किया

गया स्टैम्प शुल्क 12,68,375/- रु० है, अतः विनिर्मित एवं बिक्री किए गए नगों की अधिकतम संख्या 2,53,675 रही होगी। अतः याचिकाकर्ता कंपनियों का यह दावा कि उन्होंने 43,80,060 नगों का विनिर्माण किया, तथ्यपरक रूप में गलत है।

याचिकाकर्ता के विचार

15. वर्तमान याचिका एफ एम आई लि०, लुधियाना और फ्रीमैन्स मीज़र्स लि०, लुधियाना द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तु के दो और उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता भारतीय उत्पादनका एक बड़ा हिस्सा हैं।

16. स्कनन और क्लास द्वारा याचिका के लिए व्यक्त किया गया समर्थन नियम 5(3) के अंतर्गत नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है। तथापि, आगे यह अर्थ निकालने के लिए कि ये कंपनियां तत्पश्चात् समस्त संगत सूचना भी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हो जाएंगी, से यह अभिप्राय है कि इन कंपनियों को विधितः याचिकाकर्ता होना चाहिए। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि नियमों में दो स्थितियों - याचिकाकर्ता तथा विरोधकर्ता उत्पादक का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी किसी स्थिति में समर्थन अथवा अन्यथा के बारे में विधिक प्रावधान बेकार हो जाएंगे।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का तात्पर्य संपूर्ण रूप से घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबद्ध किसी भी क्रियाकलाप में कार्यरत हैं अथवा वे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा बनता है लेकिन इसमें ऐसे उत्पादक शामिल नहीं होंगे जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं या स्वयं उसके आयातक हैं। ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

18. ऊपर दी गई घरेलू उद्योग की परिभाषा को डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो निम्नानुसार है

.....किसी आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दिया गया तब समझा जाएगा यदि जिसका समर्थन उन उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50% से अधिक बनता है, जिसने आवेदन का तो समर्थन किया है अथवा विरोध किया है।

19. वर्तमान याचिका को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए एफ एम आई लि०, लुधियाना और फ्रीमैन्स मीज़र्स लि०, लुधियाना द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया है। याचिकाकर्ता कंपनियाँ उत्पादन के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का 90% हिस्सा बनाती हैं।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 50% हिस्सा है और इस प्रकार उनके पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) (क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने संबंधी योग्यता है और वे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

च. अन्य मुद्दे

21. याचिकाकर्ता दोहराते हैं कि सुदेश एंटरप्राइजेज द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जहां तक याचिकाकर्ता समझते हैं कि सुदेश एंटरप्राइजेज संबद्ध वस्तुओं का नतो निर्यातक है और न ही आयातक है। सुदेश एंटरप्राइजेज याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक का डीलर था। ऐसी स्थिति होने के कारण सुदेश एंटरप्राइजेज हितबद्ध पक्षकार नहीं है।

22. चूंकि सुदेश एंटरप्राइजेज किसी मामले में आयातित उत्पाद के व्यापार में शामिल नहीं हैं इसलिए यह एक पीड़ित पक्षकार नहीं है। इससंबंध में थियोफाइलीन और कैफाइन के मामले में सीगेट के निर्णय पर ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह माना गया था कि पक्षकार को प्रस्तावित उपायों का विरोध करने से पहले यह साबित करना होगा कि वह किस प्रकार से निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय से प्रभावित है। वर्तमान मामलों में सुदेश एंटरप्राइजेज द्वारा यह साबित करने के लिए कोई प्रयास

नहीं किया गया है कि पक्षकार प्रस्तावित उपायों से कैसे प्रभावित हुआ है और कैसे प्रस्तावित उपायों का विरोध कर सकता है।

23. केवल प्रमाणित टेपों पर विचार करने के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि यह तर्क आयातित उत्पाद पर भली-भांति लागू होता है। आयातित टेपों में से किसी टेपको भी भार एवं माप विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, तथापि याचिकाकर्ता यह मानते हैं कि यह तर्क वर्तमान जांच के आशय और उद्देश्य से असंगत है। ऐसा एक विधिवत ढंग से गठित प्राधिकरण है जो पक्षकार द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में कार्य कर रहा है। ऐसा मामला होने की वजह से निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह आशा करना अनुचित होगा कि वे मामले में हस्तक्षेप करें और कार्रवाई आरंभ कर दें।

24. यह स्ताना संज्ञित होगा कि अमोनियम नाइट्रेट के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में याचिकाकर्ता ने आयातों के अवैध होनेका मुद्दा बार-बार दोहराया था। जैसाकि आप भली-भांति परिचित हैं, उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का देश में उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है। तथापि, इस उत्पाद का आयात उर्वरक ग्रेड अमोनियम नाइट्रेड के रूप में किया गया है। यद्यपि वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा लघु मापन के जरिए ग्राहकों के साथ कथित धोखाधड़ी का है तथापि उस मामले में शामिल मुद्दा अति परिणामों का है। यह स्मरण किया जाएगा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले एक समाचार-पत्र का समाचार प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि घाटकोपर में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें अमोनियम नाइट्रेड का इस्तेमाल किया गया था। तथापि, आयातों की अवैधता के बारे में याचिकाकर्ताओं के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मुद्दे का यह मानकर अनदेखी करना पसंद किया है कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

25. मैसर्स सुदेश एन्टरप्राइजेज ने सही टेपों के साथ घटिया टेपों का मिश्रण करने का प्रयास किया था। याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद उसी यथार्थता और गुणवत्ता के अनुरूप हैं, चाहे वह सत्यापित टेप हो अथवा निर्यात हेतु टेप। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, तथापि इस तथ्य की पुनः जांच याचिकाकर्ता कंपनियों का दौरा करके की जा सकती है। यह मालूम होगा कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित विभिन्न टेपों की यथार्थता में कोई

अंतर नहीं है। वस्तुतः याचिकाकर्ता कंपनियां इस सामग्री का निर्यात असंख्य देशों को करती हैं। ऐसा संभव केवल इसके उत्पाद की गुणवत्ता एवं यथार्थता के कारण हुआ है।

26. ग्राहकों के साथ धोखा-धड़ी करने के गंभीर कथित आरोप के संबंध में याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि याचिकाकर्ता कंपनियों के इतिहास में एक भी ऐसा मामला नहीं रहा है जब किसी ग्राहक के साथ प्रयोग किए जा रहे याचिकाकर्ता के गलत टेलफों की कम आपूर्ति कर धोखाधड़ी की हो। इस प्रकार, पार्टी का यह आरोप मात्र एक आरोप है, बिना किसी साक्ष्य के है। निवेदन है कि कुप्रथा द्वारा ग्राहकों के साथ धोखा-धड़ी के फलस्वरूप कम लम्बाई वाले टेलों की आपूर्ति और गलत टेलों की आपूर्ति दो भिन्न-भिन्न मुद्दे हैं। प्रमाणिक टेलों से भी ग्राहकों के साथ धोखा-धड़ी हुई है और हो सकती है।

27. यदि पार्टी के इस दावे को स्वीकार किया जाता है कि अप्रमाणिक टेल ग्राहकों के हित में नहीं हैं तो यह निवेदन है कि आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत है क्योंकि बिक्री से पूर्व आयातित एक भी टेल की जांच नहीं करायी जाती है। बदले में याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निवेदन किया है कि वह आयातों पर ही प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करें क्योंकि इनका आयात विभिन्न पक्षकारों द्वारा बिना किसी जांच के किया जा रहा है।

28. यह तर्क दिया गया है कि आयातित टेलों का इस्तेमाल करनेका कारण यह है कि वह स्वदेश में उत्पादित टेलों की तुलना में काफी ठोस हैं। यह कथन कोरा एवं अव्यावहारिक है और इसमें कोई सत्यता नहीं है।

मैसर्स सुदेश एन्टरप्राइजेज के विचार

29. मापन टेलों जिनकी जांच नहीं की गयी है की मानक भार एवं माप अधिनियम के अंतर्गत शुल्क का भुगतान नहीं किया है, को जांच-पड़ताल से बाहर रखा जाना चाहिए।

30. यह अनिवार्य है कि मापन टेलों की जांच, मापन की शुद्धता एवं टेल की गुणवत्ता के बारे में निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। जिन टेलों की जांच नहीं की जाती है उनकी बिक्री उन ग्राहकों को की जाती है जो घटिया टेलों की खरीद करना चाहते हैं ताकि अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा सके। उदाहरणार्थ, कपड़ों के खुदरा व्यापारी ऐसे घटिया टेलों की खरीद करते हैं जिसमें 3 मीटर की लम्बाई

लिखी होती है किन्तु वास्तव में इनकी लंबाई कम होती है अर्थात् 2.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के टेपों से खुदरा व्यापारी कपड़े की कम मात्रा बेचकर परम ग्राहक को धोखा देता है। विभिन्न व्यापारों में लगे लोग इस प्रकार के टेपों की खरीदारी करते हैं। घटिया टेपों के विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने से अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की कुप्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

31. मापन टेपों की जांच की जानी चाहिए ताकि घटिया टेपों की बिक्री रोकी जा सके। इस प्रकार के टेपों की बिक्री के संवर्धन से ग्राहकों के हितों पर गंभीर चोट पहुंचेगी। यदि मापन टेप का कोई क्रेता एक ऐसा उत्पाद प्राप्त करता है जो अशुद्ध हो अर्थात् स्वीकार्य स्तरों से अधिक गलती हो जाए तो इस प्रकार के टेपों द्वारा की गयी कोई भी माप गलत होगी। घटिया उत्पादों की बिक्री करने की याचिकाकर्ता की नीति का एक प्रमुख कारण यह है कि कई ग्राहक आयातित टेपों का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं क्योंकि वे शुद्ध होते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा बेचे गए घटिया टेप अपर्याप्त गुणवत्ता के हैं।

32. मानक भार एवं माप अधिनियम के अंतर्गत जांच से बचने के याचिकाकर्ता के दो लक्ष्य हैं अर्थात् उन ग्राहकों की सेवा करना जो अशुद्ध टेप खरीदना चाहते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत जांच शुल्क के भुगतान से बचना भी। इस प्रकार की कम्पनियों को संरक्षण देना सरकार की नीति के विरुद्ध होना चाहिए क्योंकि इससे उनकी कुप्रथाओं को बढ़ावा ही मिलेगा। शुल्क लगाने से आम आदमी को शुद्ध मापन टेपों की उपलब्धता कारगर ढंग से बाधित होती है।

छ. प्राधिकारी द्वारा जांच एवं जांच परिणाम

33. प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच कर ली गयी है और इन जांच परिणामों तक पहुंचते वक्त उन पर विचार किया गया है तथा तत्पश्चात् जहां कहीं उचित पाया गया वहां कार्रवाई की गयी है।

34. उपर्युक्त नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अनुरोध पर उन नए निर्यातकों के मामलों पर विचार करना चाहिए जिन्हें कीमत संबंधी वचनबद्धता देने के इच्छुक बताया गया है।

35. मैसर्स सुदेश एन्टरप्राइजेज मापन टेपों का एक आयातक नहीं है और उसने आयातकों की प्रश्नावली में निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह बात नोट

करते हैं कि वे भारत में मापन टेपों के थोक एवं खुदरा बिक्रेता है। विभिन्न मुद्दों पर किए गए तर्कों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गयी है किन्तु उठाए गए अधिकांश मुद्दे या तो असंगत हैं या वर्तमान मामले में उनके तर्कों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ संगत नहीं है। मानक भार एवं माप अधिनियम के अंतर्गत शुल्कों का भुगतान न करने के बारे में उठाए गए मुद्दे को आवश्यक कार्रवाई हेतु उचित प्राधिकारी के पास उठाया जाना चाहिए। पाटनरोधी उपाय उन पाटित आयातों के कारण हो रही कीमत विकृति की जांच करने के लिए किए जाते हैं जो बदले में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच-पड़ताल में पाटित आयातों के कारण हुए नुकसान की जांच होती है।

ज. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटीकरण विवरण के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. याचिकाकर्ताओं के विचार

घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की ओर से विभिन्न मुद्दों के बारे में 11 अगस्त, 2003 के प्रकटीकरण विवरण सं० 14/31/2002-डीजीएडी के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की थी।

37. समान वस्तु:

समान वस्तु के मुद्दे के विरुद्ध किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। अतः हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस बारे में प्रारंभिक जांच-परिणामों की पुष्टि करने का अनुरोध करते हैं।

38. घरेलू उद्योग

कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का प्रमुख हिस्सा बनता है और नियमानुसार घरेलू उद्योग बनते हैं।

39. पाटन

किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित रूप एवं ढंग से प्रश्नावली का उत्तर एवं

सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, वर्तमान जांच चीन के विरुद्ध है और चीन को नियमानुसार तब तक एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना है जब तक कि चीन का प्रतिवादी उत्पादक यह सिद्ध न कर दे कि वह बाजार अर्थव्यवस्था के पर्यावरण में कार्य कर रहा है। अतः प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करने से संतुष्ट हैं। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में किए गए सामान्य मूल्य के निर्धारण की पुष्टि की जाए।

40. अमरीकी डालर में शुल्क

यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अमरीकी डालर के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है तथापि यह निवेदन है कि अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश भी अमरीकी डालर में ही की जाए ताकि विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण संरक्षण की मात्रा में वृद्धि न हो सके। तथापि, शुल्कों को केवल कीमत संदर्भ के अनुसार ही रखा जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. इन जांच परिणामों को निकालते समय घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और उन पर विचार किया गया है तथा जहां कहीं भी उचित पाया गया, उस पर इसके बाद कार्रवाई की गई है। तथापि, हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए कुछ गंभीर मुद्दों की उचित स्थानों पर जांच की गई है।

झ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन:

सुदेश एन्टरप्राइजेज के विचार

42. मै0 स्कनन की बिक्री कीमत जांच अवधि के पूर्व तथा उसके दौरान 11 से 12 रू० के आस-पास रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा पाटन का कोई आरोप नहीं है, अतः एन आई पी सर्वाधिक सफल विनिर्माता की सामान्य बिक्री कीमत से अधिक नहीं हो सकता है। पाटन के पूर्व इस विनिर्माता के पास

लागत से कम कीमत पर बिक्री करने का कोई कारण नहीं है अतः 11 रू० से अधिक के स्तर पर एन आई पी का निर्धारण अनुचित है ।

43. याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जांच अवधि के दौरान एफ एम आई लि० ने स्पेन को 3 मीटर टेपों का निर्यात 0.21 अमरीकी डालर की सी आई एफ कीमत पर किया है । इसका अर्थ यह होगा कि कारखाना द्वार पर कीमत लगभग 8 रुपये (0.16 अमरीकी डालर) प्रति नग है । प्रारंभिक जांच परिणामों में निर्धारित 4.08 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. की एन आई पी की तुलना में पहुंच कीमत लगभग 2.08 प्रति कि.ग्रा. होगी । एन आई पी को तथ्यों के संगत एक युक्तिसंगत और उचित स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता है ।

याचिकाकर्ता के विचार

44. वर्तमान जांच चीन के विरुद्ध है और चीन को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाएगा जब तक कि चीन का कोई उत्पादक यह स्थापित नहीं कर देता कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाली स्थितियों में प्रचालन कर रहा है । अतः प्राधिकारी का सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करना पूरी तरह से उचित है । प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में उत्पादन की परिकल्पित लागत के आधार पर किया है ।

45. यद्यपि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही अमरीकी डालर के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है तथापि यह निवेदन किया गया है कि अंतिम शुल्कों की सिफारिश भी अमरीकी डालर के रूप में ही की जाए ताकि विनिमय दर में परिवर्तन के कारण सुरक्षा की मात्रा का क्षरण न हो । तथापि, शुल्कों को संदर्भ कीमतों के रूप में ही रखा जाए ।

46. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सभी टेप इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी विनिर्देशनों के अनुरूप हैं । इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित टेप ईईसी के स्टील टेपों के लिए वर्ग II विनिर्देशनों के और फाइबर ग्लास टेपों के लिए वर्ग III के विनिर्देशनों के अनुरूप हैं । वस्तुतः प्रीमैन् ईईसी अनुमोदन को प्राप्त करने वाले प्रथम गैर-यूरोपीय ब्रांडों में से या जो इस तथ्य का प्रमाण है कि टेप मापदंड सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं । इस उद्योग में 'प्रीमैन्स'

वह नाम है जिस पर भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वास किया जाता है। याचिकाकर्ता गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं रखते हैं। वस्तुतः, वे यूरोप और यू एस जैसे विकसित देशों सहित विश्व में 60 से अधिक देशों को निर्यात करते हैं। लगाए गए आरोप का कोई आधार नहीं है।

47. इस तर्क में कि एक टेप में मात्र 3 या 4 भाग होते हैं, उत्पाद के बारे में संपूर्ण समालोचना की कमी है। अधिकारियों ने पहले ही याचिकाकर्ता कंपनियों का दौरा किया है और संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को देखा है। यद्यपि मेज़रिंग टेप के उत्पादन और बिक्री में बहुत सारे भाग शामिल हैं तथापि याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित मापदंडों के क्षेत्र में कम से कम महत्वपूर्ण भागों को विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

48. पाटन मार्जिन के अलग-अलग मूल्यांकन के बारे में याचिकाकर्ता यह निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता यू एस ए द्वारा बाल-बियरिंग्स और उसके हिस्सों के पाटन की जांच पर विश्वास कर रहे हैं। यह देखा जाएगा कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित मापदंडों के क्षेत्र में भाग/घटक शामिल हैं तथापि ऐसे भागों के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित नहीं किए गए हैं।

49. भागों/घटकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता इस कड़ी हुई कि टेपों को जोड़ने में अल्प समय, प्रयास और साधनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति होने के कारण, यदि भागों या घटकों पर पाटनरोधी शुल्क को न लगाया जाए तो सारी कार्रवाई निरर्थक हो जाएगी।

50. लागत स्टैम्पिंग के बारे में याचिकाकर्ता प्राधिकारी के विचारों का संदर्भ लेना चाहते हैं जब माननीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्यों वे कीमतों को कम नहीं कर सकते और प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने ध्यान दिलाया था कि आयातित टेपों की पहुंच कीमत 3-4 रुपये प्रति नग (3 मीटर टेप) तक कम है। इसकी तुलना में टेपों की उत्पादन और बिक्री लागत को छोड़कर भी 2-5 मीटर के लिए प्रत्येक टेप पर अदा की जाने वाली स्टैम्पिंग फीस 6.25 ₹ से लेकर 50 मीटर टेप के लिए 62.50 ₹ प्रति नग तक अधिक है।

51. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच किया जा रहा मुद्दा यह है कि क्या भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटन कीमतों पर हो रहा है और क्या ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक हानि हो रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी याचिकाकर्ता तथा मै0 सुदेश एन्टरप्राइजेज लि0, दोनों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 सुदेश एन्टरप्राइजेज ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया बल्कि प्रारंभिक जांच परिणामों पर तर्क दिया, जिन पर उचित स्थानों पर, जहां कहीं भी वे जांच परिणामों पर प्रभाव डालते हैं, कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति-रहित कीमत का निर्धारण कच्ची सामग्रियों, उपयोगिताओं एस जी ए और अनुमानित लाभों, जिनका किसी उद्योग द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, के सर्वोत्तम खपत प्रतिमान का ध्यान रखते हुए किया गया है। पाटनरोधी जांच का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों द्वारा पाटित आयातों के कारण क्षति के प्रभाव की जांच करना है।

53. धारा 9 क (1)(ग) के अंतर्गत, किसी मद के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

(i) समान वस्तु के लिए सामान्य व्यापार के रूप में तुलनीय मूल्य जब वह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपयोग के निमित्त हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया हो, या

(ii) जब सामान्य व्यापार के रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब उसका निर्यात, निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उपयुक्त अन्य देश से किया जाए जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए: या

(ख) उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त राशि जोड़ी गई हो जिसका निर्धारण उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए ।

54. बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से इतर देश से किया गया हो जहां वस्तु को निर्यात वाले देश से होकर केवल यानान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात वाले देश में उत्पादन नहीं किया जाता है या निर्यात वाले देश में कोई भी तुलनात्मक कीमत नहीं हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

55. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे के संबंध में विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचनाओं, दिनांक 15 जुलाई 1999 की अधिसूचना सं० 44/99(एनटी), दिनांक 31 मई, 2001 की अधिसूचना सं० 28/2001 (एनटी) और दिनांक 4 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं० 1/2001 (एन टी) को भी नोट करते हैं ।

56. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निर्यातकों को जांच के संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा उपरोक्त धारा के अनुसार अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अवसर दिया था । प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास/उच्च आयुक्त/प्रतिनिधि को भी लिखा था । प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क(1)(ग) के अनुसार निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजी थीं । सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारण को निम्नानुसार दर्शाया गया है ।

क. सामान्य मूल्य

57. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को प्रश्नावलियाँ भेजी ।

58. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में जांच के उद्देश्य हेतु प्राधिकारी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है । इस असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के इस दावेका समर्थन करते हैं कि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों पर

गैर-बाजार सिद्धांत के आधार पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए गैर बाजार अर्थव्यवस्था का किसी भी निर्यातक ने खंडन नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न जांच परिणामों के आधार परचीन जन.गण. के संबंध में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में दावा किया है। अतः प्राधिकारी ने गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे का निर्यातक द्वारा खंडन न किए जाने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत निर्यातक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है और इस प्रकार प्राधिकारी को व्यापारजांच की सामान्य प्रक्रिया लागू करने की अनुमति नहीं है, पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के नुसार उचित समायोजनों के साथ परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर स्टील मेज़रिंग टेप और फाइबर ग्लास के मेज़रिंग टेप, दोनों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का संदर्भ लिया है।

59. प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए स्टील मेज़रिंग टेप के लिए *** डालर/किग्रा के सामान्य मूल्य तथा फाइबर ग्लास के मेज़रिंग टेप के लिए *** डालर/किग्रा के सामान्य मूल्य का संदर्भ लिया है।

ख. निर्यात कीमत

60. प्राधिकारी ने नोट किया कि स्टील मेज़रिंग टेप और फाइबर ग्लास के मेज़रिंग टेप दोनों के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। चूंकि निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए अनुसार समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तर्देशीय भाड़े तथा पत्तन व्यय के लिए क्रमशः *** डालर/किग्रा*** डालर/किग्रा, *** डालर/किग्रा, *** डालर/किग्रा तथा *** डालर/किग्रा का समायोजन किया गया है।

61. अंतिम निर्धारण के उद्देश्य हेतु स्टील मेज़रिंग टेप के लिए कारखाना निर्यात कीमत का *** डालर/किग्रा तथा फाइबर ग्लास मेज़रिंग टेप के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का *** डालर/किग्रा के रूप में संदर्भ लिया गया है।

य. पाटन, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना

62. तुलना से संबंधित नियम में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

63. " पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी ।

64. जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी । उक्त अंतर में शामिल है-बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर, वास्तविक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अंतर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं ।"

65. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I में निर्धारित किए अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाकर संगत नीति का पालन किया है । प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के पाटन मार्जिन के मूल्यांकन हेतु जांच अवधि में भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत कारखाना द्वार निर्यात कीमत से की है ।

निर्यातक/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

देश	सभी निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (डालर/किग्रा)	कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत (डालर/किग्रा)	निर्यात कीमत के % के रूप में पाटन मार्जिन
चीन जन.गण.	(स्टील टेप)	***	***	1069%
	(फाइबर ग्लास टेप)	***	***	148%

उपरोक्त सभी पाटन मार्जिन न्यूनतमसीमा के ऊपर हैं ।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के विचार

66. घरेलू उद्योग ने जिस कीमत पर वस्तु का निर्यात किया है वह क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए संगत आधार नहीं है। क्षतिरहित कीमत उत्पादन की लागत पर आधारित होनी चाहिए। बिक्री कीमत, क्षतिरहित कीमत के लिए परिमापक नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के मामले में भी निर्यात कीमत लाभकारी कीमत नहीं है। तथापि, यदि याचिकाकर्ता निर्यातों को कम करते हैं तो उत्पादन की घरेलू लागत में और अधिक वृद्धि होगी। कुल उत्पादन पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता ने उत्पादन की औसत लागत निकाली है, जिसके आधार पर क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है।

सुदेश एंटरप्राइजेज के विचार

67. पिछली अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान मात्रा तथा बिक्री कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण किसी भी विनिर्माता को क्षति नहीं पहुंची है। इस संबंध में कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। उपरोक्त कारणों के आधार पर हमारा निवेदन है कि चीन से मेज़रिंग टेप के आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

68. प्रारंभिक जांच में, सिफारिश किया गया शुल्क, पहुंच मूल्य तथा 4.106 अम.डा./ कि.ग्रा. के बीच का अंतर है। चूंकि पॉकेट टेप का औसत भार लगभग 100 ग्राम है, इसलिए इकाई कीमत 0.41 अम.डा./नग होगी। आधार शुल्क तथा उतराई शुल्क को अलग करने के बाद गैर-पाटित/क्षतिरहित आयात कीमत 0.30 अम.डा. के लगभग होगी। निवेदन किया गया है कि दोनों मार्जिनों में से निम्नतम अर्थात् पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन पर शुल्क लगाया जाए। वर्तमान मामले में, एफ एम आई लि० ने जून तथा जुलाई 2002 में स्पेन को 3 मी. टेप के लिए लगभग 0.21 अम. डा. की इकाई कीमत पर निर्यात किया है। इसलिए क्षतिरहित कीमत 0.21 अम.डा. से अधिक नहीं हो सकती, विशेषकर, तब जब इस आंकड़े में विदेशी भाड़ा तथा बीमा भी शामिल है। इसलिए सिफारिश किया गया शुल्क काफी अधिक है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

69. प्रारंभिक जांच के पैराग्राफ 6 में माननीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि पिछली अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान क्षमता उत्पादन अथवा घरेलू बिक्री में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है। वास्तव में प्रारंभिक परिणामों से ही प्रकट होता है कि गिरावट, यदि हुई है तो वह 2% से 3% से अधिक नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। यह दावा कि बिक्री कीमत में गिरावट आई है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनियों ने 1997 के बाद जांच अवधि सहित दो अवसरों पर अपनी कीमतों में प्रत्येक बार 10% तक उर्ध्वगामी संशोधन किए हैं। हम यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों लाभों में वृद्धि अर्जित कर रही हैं, जिससे उनका यह दावा कि जांच अवधि के दौरान घाटों में वृद्धि हुई है, गलत साबित हो गया है। वास्तव में एफ एम आई लि०, फिरोजपुर रोड, लुधियाना के मामले में 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में कर से पूर्व, लाभ 56.32 लाख था, जो 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष में 132.82 लाख तक बढ़ गया था। 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष में यह लाभ 130.10 लाख पर उच्च स्तर पर बना रहा। इसी प्रकार, मै० प्रीमैन मेज़र लि० जुगियाना रोड, लुधियाना के मामले में 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ 41.64 लाख था, जो जांच अवधि के दौरान बढ़कर 51.23 लाख हो गया था। इस प्रकार, यह दावा कि बिक्री में गिरावट के कारण याचिकाकर्ता को क्षति हो रही है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसलिए, जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

70. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में क्षति के निर्धारण के संबंधी सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि:

71. क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयात की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी।

72. पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी द्वारा इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों के मूल्य पर प्रभाव के संबंध में नियम 19 के उप-नियम (2) पर विचार करेंगे कि क्या

भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयात द्वारा कोई महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो कि अथवा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती ।

73. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे संकेतकों यथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन पर विचार किया था ।

74. प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण करते समय क्षति संबंधी सभी संकेतकों पर विचार किया है । इसमें सभी प्रासंगिक तथ्य शामिल होंगे अर्थात् पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार की कीमतों पर उनका प्रभाव और घरेलू उत्पादकों पर उसका परवर्ती प्रभाव, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति आदि । घरेलू उद्योग की समान वस्तु के क्षतिरहित मूल्य के निर्धारण के दौरान, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत पर विचार किया जोकि मानकीकृत सर्वोत्तम उपभोग मानकों को ध्यान में रखेगा, साथ ही जांच अवधि के दौरान कच्चे माल की वास्तविक कीमत पर भी विचार करेगा, जोकि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में होगी ।

ठ. वास्तविक क्षति

75. निम्नलिखित मानदण्ड यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है:

विवरण	इकाई	1999-00		2000-2001		जांच अवधि(वार्षिकीकृत)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आयात							
चीन	किग्रा.	100283		81228		273906	
प्रवृत्ति		100		81		273	
अन्य देश	किग्रा.	1021		4790		426	
प्रवृत्ति		100		469		42	
कुल आयात	किग्रा.	101304		86018		274332	
प्रवृत्ति		100		85		271	

आर्थिक मानदंड							
क्षमता	किग्रा	989550		989550		989550	
उत्पादन		100		95		91	
क्षमता उपयोग	%	67.89		64.21		61.48	
घरेलू बिक्री		100		106		106	
निर्यात बिक्री		100		72		47	
कुल बिक्री		100	100	96	103	89.86	96.48
प्रारंभिक स्टॉक	किग्रा	17658.77		24390.95		19500.27	
प्रवृत्ति(सूची-बद्ध)		100		138		110.43	
अंतिम स्टॉक	किग्रा	24390.95		19500.27		30159.67	
प्रवृत्ति(सूची-बद्ध)		100		80		123.65	
औसत स्टॉक	किग्रा.	21024.86		21945.61		24829.97	
प्रवृत्ति(सूची-बद्ध)		100		104		118.10	
इकाई लाभ/हानि			100		54		-38
उत्पादन की इकाई लागत			100		109		110.84
इकाई विक्रय मूल्य			100		106		104.79
लगाई गई पूंजी पर आय	रु/लाख		1.72		0.92		0.62
रोजगार(सूची-बद्ध)		100		88		81.54	
वेतन एवं मजदूरी(सूची-बद्ध)		100		109		112.30	
वृद्धि	%			5.36		0.51	
मांग	किग्रा.	736076		750190		972951	
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)		100		102		132	
चीन से आयात	किग्रा.	100283		81228		273906	
अन्य देशों से आयात	किग्रा.	1021		4790		426	
कुल आयात	किग्रा.	101304		86018		274332	
मांग में हिस्सा							
घरेलू उद्योग	%	65.33		67.73		52.49	
प्रवृत्ति(सूचीबद्ध)		100		104		80.35	
अन्य उत्पादक	%	20.91		20.80		19.31	
चीन से आयात	%	13.62		10.83		28.15	
प्रवृत्ति(सूचीबद्ध)		100		79		206.64	

अन्य देशों से आयात	%	0.14		0.64		0.04	
आयात में हिस्सा							
चीन	%	99		94		99.84	
प्रवृत्ति(सूची बद्ध)		100		95		100.86	
अन्य देश	%	1		6		0.16	
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात	%	15		14		45.09	
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)		100		90		299.06	

पाटित आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा

76. संबद्ध देश से मेज़रिंग टेपों का आयात महत्वपूर्ण रूप से (i) निरपेक्षतः (ii) उत्पाद के संबंध में और (iii) भारत में उपभोग के संबंध में, बढ़ गया है। यद्यपि प्राथमिक रूप से केवल संबद्ध देश से आयात हुए हैं, जांच अवधि के दौरान भारत में मांग के संबंध में चीन से आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात बढ़ा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों का मूल्य सी आई एफ आयात मूल्य पर ध्यान में लिया गया है, यदि आयातों के मूल्य की तुलना बेसिक आयात मूल्य को जोड़कर की जाए तो भी यह हिस्सा अधिक होगा।

77. जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग घटा है। उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट इस तथ्य के बावजूद है कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी संबद्ध वस्तु के व्यावसायिक उत्पादन में अधिक पुरानी नहीं है। मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखने के बावजूद, संबद्ध वस्तु के आयात में वृद्धि की दर घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है।

78. दोनों याचिकाकर्ता कंपनियां उनकी कीमतों का निर्धारण प्रचलित बाजार दशाओं पर करती हैं। बाजार कीमतें पाटित आयातों की कम कीमतों द्वारा प्रचालित हुई थी क्योंकि पाटित आयातों का हिस्सा 2000-01 में 94% से 2001-02 में 99.94% तक बढ़ा है।

79. यद्यपि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा सीमांततः बढ़ी है तथापि बिक्री कीमत घटी है। साथ ही, घरेलू उद्योग निम्नलिखित कारणों से अपनी कीमतें पाटित आयातों की कीमतों के अनुरूप नहीं घटा सका:-

क. मेजरिंग टेप एक उपभोक्ता उत्पाद है, जो मूल रूप से खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं के लिए व्यापक स्तर पर बिक्री प्रायः नगण्य है।

(ख) उपभोक्ताओं में प्रमुखतः ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़-लिखे नहीं हैं।

(ग) आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों और उत्पादन लागत की तुलना में इतनी कम है कि घरेलू उद्योग इस स्थिति में ही कि वह आयातित टेपों की कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें कम करने के बारे में सोच सके।

(घ) स्थिति पर विचार करने पर घरेलू उद्योग के पास दो विकल्प थे या तो कीमतें अनुरूप रखना या बाजार गंवा देना। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रचलित स्थिति में घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लाम एवं बाजार दोनों गंवा दिए।

मांग में बाजार हिस्सा

80. मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा पिछले वर्ष जांच-अवधि में 67.73% की तुलना में 52.49% रह गया है। अन्य उत्पादकों ने भी केवल मामूली प्रतिशत से मांग में अपना हिस्सा गंवाया है। जबकि चीन से आयातों में उछाल पिछले वर्ष के 10.83% की तुलना में जांच अवधि में कुल मांग का 28.15% तक है। सामान्य रूप से मांग 1999-2000 में 100 से जांच अवधि में 132 तक बढ़ी है तथापि, मांग में वृद्धि पर अधिकतर चीन से हुए पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से मेजरिंग टेपों के कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का स्थान पाटित आयातों ने ले लिया है।

माल-सूची तथा संविदा गंवानेका साक्ष्य

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माल-सूची वर्ष 1999-2000 में 21024 कि.ग्रा. से घटकर वर्ष 2000-2001 में 19500 कि.ग्रा. रह गई थी। तथापि यह जांच

अवधि(वार्षिकीकृत) में महत्वपूर्ण रूप से 32159 कि.ग्रा. तक बढ़ गई है। औसत स्टॉक में भी वर्ष 1999-2000 में 21204 कि.ग्रा. से जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में 24829 कि.ग्रा० तक का बढ़ता हुआ रूख प्रदर्शित होता है। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में उत्पादन में कमी के साथ स्टॉक्स में बढ़ता हुआ रूख संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है।

82. यह दावा किया गया है कि निर्यात कीमत में गिरावट के चलते घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत को निर्यात कीमत के बराबर रखना पड़ा है और प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिक्री कीमत को इसी स्तर पर रखना पड़ा है : इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योग अपनी सीमान्त लागत भी वसूल नहीं कर पाया। आगे यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग इतनी कम कीमत पर मेजरिंग टेप को बेचने में सक्षम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उसे संविदा गंवानी पड़ी है। प्राधिकारी मानते हैं कि कम निर्यात कीमत के कारण घरेलू उद्योग को उत्पाद को घाटे में बेचना पड़ा है।

कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को किसी महत्वपूर्ण स्तर तक कम करना है। भारत में घरेलू उद्योग पर पड़े प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, बिक्रियां, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली आदि पर विचार किया है। ऐसे अनेक मापदंड हैं जो क्षति को सांख्यिकित करते हैं तो क्या वर्तमान पाटित कीमतों पर आयातों की अनुमति दी जानी चाहिए। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि दर तथा घरेलू उद्योग के लाभों में इसके अनुरूप गिरावट वे मापदंड हैं जो कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है। यह देखा गया है कि पाटन से संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अपने बाजार हिस्से को बचाने के लिए याचिकाकर्ता को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम कीमत वाले और पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। पाटित आयातों की पहुंच कीमत से भारी कीमत कटौती के साक्ष्य का संकेत मिलता है।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम कीमत पर बिक्री एक महत्वपूर्ण सूचक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की उचित विक्रय कीमत निकाली है तथा कम कीमत पर बिक्री की मात्रा ज्ञात करने के लिए इस उचित विक्रय कीमत की बाजार पहुंच से तुलना की है। विश्लेषण से कम कीमतों पर बिक्री के महत्वपूर्ण स्तर का पता चलता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आयातों का घरेलू बाजार की कीमत पर अत्यधिक दमनकारी/दबावकारी प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मद्देनजर अपने बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं है। अतः उपलब्ध साक्ष्य की जांच से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने किल मिलाकर जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की अपनी बिक्रियों पर क्षति उठाई। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की सीमा को निर्धारित किया है तथा प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण भारी कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ा है।

रोजगार

85. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर वर्ष 1999-2000 में 100 से घटकर वर्ष 2000-2001 में 88 रह गया है और यह जांच अवधि (वार्षिकीकृत) में और भी घटकर 81.54 रह गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार में यह परिवर्तन संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में कमी के कारण हुआ है और यह घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुंचा रहा है।

86. घरेलू उद्योग की उत्पादकता कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण बढ़ी है। यह भी देखा गया है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आई है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार के स्तर में इस गिरावट का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण पता नहीं लगाया जा सकता।

लाभप्रदता

87. उत्पादन की इकाई लागत वर्ष 1999-2000 में 100 से बढ़कर वार्षिकीकृत जांच अवधि में 110.84 हो गई है जबकि इकाई बिक्री कीमत भी बढ़कर 100 से 104.79 हो गई है परन्तु इकाई बिक्री कीमत उत्पादन लागत के अनुपात में नहीं

बढ़ी है जिसके कारण घाटे में वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग इस तथ्य के कारण घाटा उठा रहा है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण उसे बाजार में बने रहने के लिए बिक्री कीमत को लागत कीमत से कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है । घरेलू उद्योग ने मन्द बिक्री कीमत के कारण वास्तविक क्षति उठाई है जिसके कारण लागत कीमत की वसूली नहीं हुई तथा वित्तीय घाटा उठाना पड़ा ।

88. हालांकि बिक्री लागत, उत्पादन मूल्य और बिक्री मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री मूल्य में वृद्धि से अधिक है । इससे प्रत्यक्ष रूप से घरेलू उद्योग के लाभों में कमी आयी है ।

वृद्धि और निवेश पर आय

89. उत्पाद की मांग बढ़ी है, तथापि घरेलू उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आयी है । देश में भारी मांग के बावजूद आयात घरेलू उद्योग के विकास को बाधित कर रहे हैं । यह दावा किया गया है कि यदि संबद्ध देश से पाटित आयातों को रोकने के लिए उपचारी उपाय नहीं किए जाते हैं तो संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का लक्ष्य प्राप्त करना या बाजार सू पूंजी वसूल करना भी संदिग्ध है ।

क) घरेलू उद्योग के नकद लाभ सीमान्ततः बढ़े हैं, परन्तु जांच अवधि में निवेश पर आय और कम हो गई है ।

ख) प्रति कर्मचारी मजदूरी बढ़ी है । तथापि यह वृद्धि देश में मौजूदा श्रम कानूनों के कारण अधिक है । इसके अलावा मजदूरी में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री लागत में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग अपने लाभों को कायम नहीं रख पाया ।

ग) घरेलू उद्योग की संवृद्धि में कमी हुई है ।

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संगत कारक संचयी और समग्र रूप से यह निर्धारित करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

ड. कारणात्मक संबंध

91. यह निर्धारित करने में कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया है:-

92. पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के अत्यधिक आयातों ने घरेलू उद्योग को इसकी बिक्री कीमतों को अलाभकारी स्तर तक कम करने को बाध्य किया है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति उत्पन्न हुई है ।

93. संबद्ध देश से आयातों ने भारतीय बाजार में कीमतों को ऐसे स्तर तक कम कर दिया है कि घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री से अपनी पूरी उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ प्राप्त नहीं कर पाया था ।

94. संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत कम करने को बाध्य किया है, जिसके चलते उसकी लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है ।

95. अतः प्राधिकारी उपरोक्त से यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर किया गया है । इसके अलावा भारत में हुए आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर किए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने निवेशों पर तर्कसंगत आय अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है । ये मापदंड संचयी और समग्र रूप से यह दर्शाते हैं कि पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ता को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

96. कुल खपत में पाटित आयातों की मात्रा का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 10.83% से बढ़कर जांच अवधि में 28.15% हो गया है । घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा वर्ष 2000-01 में 67.73% से कम होकर जांच अवधि में 52.49% रह गया है । पाटित आयात भारत में ऐसी कीमत पर आ रहे थे जिनकी वजह से समान घरेलू उत्पाद की कीमतों में काफी कटौती करनी पड़ी । पाटित आयातों की कीमतों की वजह से समान घरेलू उत्पादों की कीमतें अवरूद्ध और कम हुई । इस प्रकार मात्र व कीमत संबंधी दोनों प्रभाव सिद्ध हो जाते हैं ।

97. मांग में कमी नहीं हुई (अपितु मांग बढ़ गई है) । इसके अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई कारण नहीं है जैसे कि व्यापार प्रतिबंधक प्रथा या प्रौद्योगिकी में विकास,

जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। आयातों में समग्र रूप से वृद्धि जो भारत में उत्पादन तथा खपत से संबंध रखती है, के परिणामस्वरूप बिक्री में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप देश में घरेलू उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त पाटन की कम कीमतों से घरेलू उद्योग अपनी इष्टतम लाभप्रदता से वंचित हुआ है।

ढ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मामले

98. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली व उचित प्रतियोगिता की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है।

99. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले उत्पादों के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है और उसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डाल सकता है। तथापि इन पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों के किए जाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को हटाया जाएगा तथा घरेलू उद्योग का पतन रुकेंगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित भी नहीं होंगे इसलिए उपभोक्ताओं की उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

101. प्राधिकारी ने उचित बिक्री कीमत के संबंध में केवल याचिकाकर्ता के प्रस्तुतीकरणों पर विश्वास नहीं किया है बल्कि मेजरिंग टेपों की विभिन्न किस्मों की लागत एवं विनिर्माण प्रक्रिया की मौके पर जांच एवं सत्यापन के लिए एक टीम को प्रतिनियुक्त किया है और ब्यौरे-वार ढंग से घरेलू उद्योग के लिए अलग से भारत में मेजरिंग टेपों की उचित बिक्री कीमत निकाली है।

ण. निष्कर्ष

102. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) संबद्ध देशों से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है:
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है :
- (iii) यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

103. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन उक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या इससे कम के पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया गया तो इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए निर्धारित भारत औसत क्षतिरहित कीमत के साथ की है ।

104. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमा शुल्क शीर्ष 9017,9017.80,9017.8001,9017.90 के अंतर्गत आने वाले संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निम्नांकित ढंग से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क निम्नांकित तालिका के कालम सं0 9 में उल्लिखित राशि तथा नीचे उल्लिखित संबद्ध क्षेत्र/देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों के अमरीकी डालर प्रति किग्रा. पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा:

क्र. सं.	उप शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन 1	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	9017,9017.80,9017.8001,9017.90	मेजरिंग टेप	स्टील टेप एवं उनके हिस्से एवंघटक	चीन जन.गण	कोई निर्यातक	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	4.106	कि.ग्रा.	अम.डा
2.	9017,9017.80,9017.8001,9017.90	मेजरिंग टेप	स्टील टेप एवं उनके हिस्से एवंघटक	कोई देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	4.106	कि.ग्रा.	अम.डा
3.	9017,9017.	मेजरिंग	स्टील	चीन	चीन	कोई भी	कोई भी	4.106	कि.ग्रा.	अम.डा

	80,9017.80 01,9017.90	टेप	टेप एवं उनके हिस्से एवं घटक	जन. गण	जन. गण.	उत्पादक	निर्यातक			
4	9017,9017. 80,9017.80 01,9017.90	मेजरिंग टेप	फाइबर ग्लास टेप एवं उनके हिस्से एवं घटक	कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	4.691	कि.ग्रा.	अम.डा
5	9017,9017. 80,9017.80 01,9017.90	मेजरिंग टेप	फाइबर ग्लास टेप एवं उनके हिस्से एवं घटक	चीन जन. गण.	कोई भी निर्यातक	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	4.691	कि.ग्रा.	अम.डा
6	9017,9017. 80,9017.80 01,9017.90	मेजरिंग टेप	फाइबर ग्लास टेप एवं उनके हिस्से एवं घटक	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	4.691	कि.ग्रा.	अम.डा

105. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्कों के अतिरिक्त सभी सीमा शुल्कों द्वारा यथा निर्धारित कर निर्धार्य मूल्य होगा।

106. उपरोक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी दिनांक 8 जनवरी, 2003 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

107. इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार दायर की जा जा सकेगी।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2003

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation concerning import of measuring tapes originating in or exported from China PR - Final Findings.

No. 14/31/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:
 - (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification No. 14/31/2002-DGAD dated the 31st January 2003 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Measuring Tapes originating in or exported from China PR and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
 - (ii) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;
 - (iii) The Authority also forwarded copy of the Preliminary Findings to the Embassy/High Commission/Representative of subject country in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings;
 - (iv) The Authority held a public hearing on 1st May 2003 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, user industries and user industries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. Designated Authority has considered the written submissions thus received from interested parties in these findings;

- (v) The Authority made the public file available to all interested parties containing non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties, for inspection, upon request;
- (vi) Arguments raised by interested parties before announcing of Preliminary Findings, which have been brought out in the Preliminary Findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity. However, arguments raised after the preliminary findings by the interested parties have been appropriately dealt with in the Preliminary Findings and/or these findings;
- (vii) In accordance with Rule 16 of the anti dumping Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (viii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 30th June 2002;
- (ix) **** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES:

VIEWS OF M/S Sudesh Enterprises

2. In the preliminary findings product under consideration has been defined as measuring tapes and its parts and components. Neither the preliminary findings nor the petition have cared to identify or give names of the parts or components which are sought to be covered by these findings. It is submitted that a steel strip acquires the characteristics of a component part of a measuring tape only after certain processes are carried out. In absence of identification of the parts and components, their quantum of imports, no conclusion can be reached that the parts have been imported at dumped prices or that they caused injury to the petitioners.

3. From the preliminary findings, it appears that the normal value has been calculated only for steel tape and fibreglass tapes however normal value has not been calculated for the parts/components. Similarly the export price is only for the tapes and not the parts. In the absence of determination of the dumping and injury margin, the recommendation of duty is not justified.

VIEWS OF PETITIONERS

4. The product under consideration in the present petition is Measuring Tapes and its parts and components thereof so long as imports of parts and components constitute imports of Measuring Tapes. Measuring Tapes produced by the domestic industry and Measuring Tapes imported from China are comparable in terms of

characteristics such as physical & Chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

5. The product under consideration is “Measuring Tapes”, its parts and components etc., all type of steel measuring and fibre glass tapes and their parts or components are the subject matter of the present petition. It is generally used for measuring the length, breadth etc. of an object. It is used by foreman, mason, carpenter, forestry departments and tailors etc. Measuring Tapes are manufactured from tempered high quality carbon steel blade, phosphated and coated with special enamel to withstand corrosion and rust. Measuring tapes are used for :-

- a. high precision professional jobs;
- b. measuring depth, width, or length of an object;
- c. contraction and surveys.

6. In technical terms the measuring tapes are defined in terms of length and width of a tape, raw material used i.e. steel or fibre glass and, finally precision with which dimensions are marked on the tape. It is classified under Chapter 90 of the Customs Tariff Act under sub-headings 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90. The petitioner has stated that subject goods are being imported under above-mentioned sub-headings. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

7. There is no known difference in subject goods produced by the Indian industry and imported from China PR. Subject goods produced by the Indian industry and imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as product specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Subject tapes produced by the petitioners and imported from China PR should be treated as like articles in accordance with the anti dumping Rules.

8. There is no known difference in the technology adopted by the domestic industry and the manufacturers in China. The technology adopted by the domestic industry is comparable to the technology adopted by the manufacturers in China. However, every manufacturer fine-tunes its production process on the basis of necessities and available facilities.

9. The Authority notes that the investigation covers all types of steel measuring and fibre glass tapes and their parts, components and constitute the subject matter under investigation. The Authority for the purpose of dumping margin has made appropriate comparisons on kg basis only. The Authority also holds that the goods produced by the Domestic Industry and those exported from the subject country are like article within the meaning of the Rules 2(d).

D. DOMESTIC INDUSTRY**VIEWS OF M/S Sudesh Enterprises**

10. All the petitioners and supporters of the request for duty are liable to be excluded whereas M/s. Skanan have themselves imported tapes during the period of investigation, the others have imported components from China. Since both the tapes and components are the product under consideration, there is no domestic industry and the petition is liable to be dismissed.
11. We also submit that a simple letter is not sufficient for showing support, the manufacturers such as M/s. Skanan and M/s. Klas must co-operate with the Hon'ble Designated Authority by providing the relevant information regarding its production, sales, cost of manufacture and imports. In the absence of such co-operation, companies such as M/s. Skanan and M/s. Klas should not be permitted to participate in the proceedings.
12. M/s. Klas are to be excluded, as they are not a manufacturer of measuring tape. They are selling only uncalibrated measuring tapes that are tapes on which there are no makings. Tapes without marking are not measuring tapes, since they can not be used for measurement purposes.
13. In the preliminary findings, in paragraph B (b) it has been stated that the total domestic production is 608343 Kgs and the petitioner companies constitute 90% of the subject goods production. Therefore, the petitioner companies claim that their production during the period of investigation was 547508 Kgs. Since this production, we presume, has been indicated for the period of investigation (15 months), the production for 12 months period on a pro-rata basis would be 438006 Kgs. Normally, measuring tapes are of various types and sizes. The weight of the measuring tapes varies from size to size. In the petition, it has been stated that the large majority of the production is of pocket measuring tapes of a length of 3 Mtrs. The weight of one piece of a pocket type measuring tape of 3 meters is about 100g. Therefore, on the basis of the weight indicated the production of the petitioner companies should have been of 43,80,060 pieces. We believe that this quantity of tapes has not been manufactured by the petitioners, since in the balance sheet for the period 2001-2002 the figures indicated towards payment of weights and measurement charges are for a much smaller quantity.
14. Under the Standards of Weights and Measures Act, 1976 read with the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 every weight or measure is to be verified and stamped by Jurisdictional Inspector. In the schedule to the Act the charges for such verification and stamping have been indicated. These charges vary based on the length and type of measuring tape. The applicable charge in the case of pocket tapes of 3 Mtrs. Length for sales outside the State of Punjab, is Rs. 6.25 per piece. As regards sales made within the State of Punjab, the applicable charges is Rs. 5 or above in the case of plastic and steel pocket type of 3 Mtrs as per

Notification dated 13th March 2002. In the balance sheet profit and loss for the year 2001-2002 the weight and measure charges are shown as Rs. 14,34,300/- in the case of M/s. Freemans Measure Ltd., Jugiana Road, Ludhiana. This would mean sales of about 2,86,860 pieces only. Similarly in the case of FMI Limited, Ferozpur Road, Ludhiana the stamp duty paid is of Rs. 12,68,375/-, therefore the maximum number of pieces that could have been manufactured and sold would be 2,53,675. The claim that the petitioner companies have manufactured 43,80,060 number of pieces is therefore factually incorrect.

VIEWS OF PETITIONERS

15. The present petition was filed by FMI Limited, Ludhiana and Freemans Measures Limited, Ludhiana. Apart from the petitioners, there are two other producers of the subject goods in India. Petitioners account for a major proportion of Indian production.

16. The support to the petition expressed by Skanan and Klas is to meet the requirement of the Rules under Rule 5(3). However, to construe further that these companies would then be obliged to provide all relevant information also is tantamount to saying that these companies should de factor become petitioners. Should the argument be accepted, it would imply that the Rules should provide for two situation – petitioner and opposing producers. The legal provisions relating to support or otherwise in such an event would become infructitious.

E. EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

17. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, “domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry.”

18. The definition of Domestic Industry given above is further clarified by Rule 5 of Rules which reads as follows:-

“----- the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.

19. The present petition has been jointly filed by FMI Limited, Ludhiana and Freemans Measures Limited, Ludhiana., representing the domestic industry and the Authority has considered the information supplied by these two above mentioned

companies for the purpose of Anti Dumping investigations. The petitioner companies constitute 90% of the subject goods under consideration.

20. The Authority notes that the petitioners constitute more than 50% of the total domestic production of the subject goods and, therefore, have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5 (3) (a) and (b) of the Anti-Dumping Rules and also represent Domestic Industry in terms of Rule 2(b)

F. OTHER ISSUES

VIEWS OF PETITIONERS

21. Petitioners reiterate that no questionnaire response has been filed by Sudesh Enterprises. As far as the understanding of the petitioners goes, Sudesh Enterprises is neither an exporter nor an importer of the subject goods. Sudesh Enterprises was a dealer of one of the petitioner companies. Such being the case, Sudesh Enterprises is not an interested party.

22. Since Sudesh Enterprises is not dealing in the imported product, in any case, it is not an aggrieved party. Kind attention is invited to the CEGAT decision in the matter of Theophylline and Caffeine, wherein it has been held that a party must establish how it is aggrieved with the decision of the Designated Authority, before it can oppose the proposed measures. In the instant case, no efforts have been made by Sudesh Enterprises to establish how the party is aggrieved with the proposed measures and how it can oppose the proposed measures.

23. With regard to consideration of only verified tapes, it is submitted that the argument holds good for the imported product also. Not even a single imported tape is verified by Weights & Measures Deptt. however, petitioners consider that this argument is extraneous to the intent and objective of the present investigations. There is a duly constituted authority who is handling the issue raised by the party. Such being the case, it would be improper to expect the Designated Authority to step into their shoes and start discharging that function.

24. It would be relevant to point that in the matter of anti dumping investigations relating to imports of Ammonium Nitrate, petitioners repeatedly brought in the issue of illegality of imports. As you are well aware, ammonium nitrate as a fertilizer is banned for production and sale in the Country. However, the product has been imported as fertilizer grade ammonium nitrate. While the issue involved in the present case is that of alleged duping of the customers by short measurement, the issue involved in that case is of far higher consequences. It would be recalled that a newspaper news item was earlier filed by the petitioners, which stated that the Bomb Blast at Ghatkopar was set off using ammonium nitrate. However, in spite of repeated submissions of the petitioners about illegality of imports, the Designated Authority has chosen to ignore this issue, presumably for the reason that there is a competent authority to consider that issue.

25. M/s. Sudesh Enterprises has attempted to mix the non-standards tapes with inaccurate tapes. Petitioners submit that all the products produced by the petitioners conforms to the same accuracy and quality parameters, be it verified tapes or tapes meant for exports. Petitioners submit that even though the data furnished by the petitioners has already been verified by the Officers, this fact can again be verified by visiting the petitioner companies. It would be found that there is no difference in the accuracy of the various tapes produced by the petitioner companies. In fact, petitioner companies export the material to a large number of countries. This has been possible only due to the quality and accuracy of its product.

26. With regard to wild allegation of duping customers, petitioners submit that there has not been even a single such case since the history of the petitioner companies when any consumer was cheated with short supply due to inaccurate petitioner's tapes being used. Thus, the allegation of the party is a mere allegation, unsubstantiated with any evidence. It is submitted that duping consumers by malpractice resulting in supply short of lengths and inaccurate tapes are two difference issues. Even with verified tapes, consumers have been and can be cheated/duped.

27. If the contention of the party that unverified tapes are not in the consumers interest is to be accepted, it is submitted that this calls for complete ban on imports as not even a single imported tape is verified before sale. Petitioners, in the alternate, requests the Designated Authority to recommend banning the imports itself, as these are being made by various parties without any verification.

28. It has been argued that the reasons for use of imported tapes is that they are fairly precise as compared to domestically produced tapes. The statement is bald and wild with no basis and truth in it.

VIEWS OF M/S Sudesh Enterprises

29. Measuring Tapes, which have not been verified, and no fees paid under the Standards of Weights and Measures Act should be excluded from consideration.

30. It is mandatory that the measuring tapes should be verified by the Inspector with regard to accuracy of measurement and quality of tape. Tapes, which are not verified, are sold to customers, who want to purchase non-standard tapes so as to dupe their customers. For e.g., retailers of fabrics purchase non-standard measuring tapes which are marked as 3 meters but are actually of a lower length, that is 2.5 meters. With such tapes, the retailer is able to dupe the ultimate consumer by selling a lower quantity of fabric. Persons in various trades purchase this type of tape. Providing protection to manufacturers of non-standard tapes will amount to encouragement of such malpractices in the economy.

31. The measuring tapes should be verified so as to prevent sales of non-standard tapes. The promotion of sale of such tapes will seriously hamper consumer interests. If a purchaser of measuring tape, obtains a product, which is inaccurate, that is the level of error exceeds the permissible levels, any measurement taken with such tapes will be

incorrect. The policy of the petitioner to sell non-standard products is one of the main reasons why many customers prefer to use imported tapes, as they are fairly precise. The non-standard tapes sold by petitioner are not of adequate quality.

32. The motive of the petitioners to avoid verification under the standards of Weights and Measures Act is two fold – that is to cater to customers who wish to buy inaccurate tapes and also to avoid payment of verification fees under the Act. Providing protection to such companies should be against the government policy, as it would only encourage their malpractices. The imposition of duty effectively bars the availability of accurate measuring tapes to the common man.

G. EXAMINATION AND FINDINGS BY THE AUTHORITY:

33. The submission made by the users, domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate, have been dealt hereinafter.

34. The cases of new exporters of those stated to be willing to give price undertaking should be considered, on request to the Authority in accordance with the Rules Supra.

35. M/s. Sudesh Enterprises Ltd., is not a importer of measuring tapes and did not file the submission in the importers questionnaire. The Authority notes that they are the whole sellers and retailers of measuring tapes in India. The arguments raised on various issues have been examined by the Authority but most of the issues raised are either extraneous or not relevant for the purpose of considering their argument in this instant case. The issue raised regarding non-payment of fees paid under the Standards of Weights and Measures Act should be taken up at the appropriate Authority for necessary action. The anti dumping measures are provided to look into the price distortion-taking place due to the dumped imports which is further causing injury to the domestic industry. Therefore the Authority notes that anti dumping investigation examines the injury caused due to the dumped imports.

H. VIEWS OF INTERESTED PARTIES ON DISCLOSURE STATEMENT ISSUED BY THE DESIGNATED AUTHORITY:

36. VIEWS OF PETITIONERS

The domestic industry filed their comment on the disclosure statement No. 14/31/2002-DGAD dated 11th August 2003, with regard to various issues on behalf of the domestic industry.

37. Like Article:

There is no issue raise by any interested parties against the issue of like article. We, therefore, request the Designated Authority to confirm the preliminary finding in this regard.

38. Domestic industry

The petitioners account for major proportion of total Indian production and constitute domestic industry in accordance to the Rules.

39. Dumping:

None of the interested parties has filed questionnaire response and information in the form and manner prescribed. Moreover, the present investigations are against China and China has to be treated as a non-market economy in accordance to the Rules unless responding producer in China establishes that it is operating in the market economy environment. The Authority is, therefore, fully justified in proceeding with the best available information. The petitioners submit that the determination of normal value done in the preliminary findings may kindly be confirmed.

40. DUTY IN US \$

Though the Designated Authority has already recommended anti-dumping duty in terms of US \$, it is submitted that the final duties may also be recommended in terms of US \$ only, so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate. However, the duties may please be kept in terms of reference price only.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

41. The submission made by the domestic industry and other interested parties have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter. However, certain crucial issues raised by interested parties have been examined at appropriate places.

I. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:**VIEWS OF SUDESH ENTERPRISES**

42. The sale price of M/s. Skanan both before and during the period of investigation has been around Rs. 11 to Rs. 12. During 2000-01, the petitioner alleges no dumping, and therefore, the NIP cannot exceed the normal sale price of the most efficient manufacturer. Prior to the dumping, there is no reason for this manufacturer to sell below cost, therefore, the determination of NIP at level higher than Rs. 11 is unjustified

43. It is admitted by the petitioner that FMI Ltd., has made exports at a CIF price of US\$ 0.21 to Spain for 3 meter tapes during the POI. This would mean that the ex-factory price is about Rs. 8 (US\$ 0.16) per piece. The landed value would come to around 2.08 per Kg as against the NIP determined in the preliminary findings at over US\$ 4.08 per Kg. The NIP is required to be brought to a rational and reasonable level consistent with the facts.

VIEWS OF PETITIONERS

44. The present investigation are against China and China has to be treated as a non-market economy unless a producer in China establishes that it is operating in the market economy conditions. The Authority is, therefore, fully justified in proceeding with the best available information. The Authority has determined normal value on the basis of constructed cost of production in a market economy third country in the preliminary findings.
45. Though the Designated Authority has already recommended anti dumping duty in terms of US\$, it is submitted that the final duties may also be recommended in terms of US\$ only, so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate. However, the duties may please be kept in terms of reference price only.
46. All tapes produced by the petitioners conform to International Organization of Legal Metrology specifications. Further, tapes produced by the petitioners conform to class II EEC specifications for steel tapes and class III specifications for fiberglass tapes. In fact, Freeman was amongst the first non-European brands to obtain EEC approval, which is a testimony of the fact that the tape measures conform to the best international quality standards. "Freemans" is name to be reckoned upon in this industry not only in India but also internationally. Petitioners maintain most modern facilities for producing quality product. In fact, they export to more than 60 countries in the world – including developed countries such as Europe and US. There is no basis for the allegation made.
47. The arguments that a tape consists of 3 or 4 parts only lacks complete appreciation about the product. The Officers have already visited the petitioner companies and have seen the entire production process. While there are a very large number of parts involved in production and sale of measuring tapes, petitioners submit that at least critical parts are required to specified in the scope of product under consideration and proposed measures.
48. With regard to separate assessment of dumping margin, petitioners wish to submit that the same is not required. Petitioners are relying upon the investigations into dumping of ball bearings and parts thereof by the USA. It would be seen that while scope of the product under consideration and proposed measures include parts/components, separate margins have not been determined for such parts.
49. Imposition of anti dumping duty on parts/components is necessitated due to the fact that assemble of tapes involves miniscule time, effort and resources. Such being the case, the entire exercise may become futile in case the anti dumping duty is not extended to parts or components.
50. With regard to cost stamping, petitioners wish to refer to the views of the Designated Authority when the Hon'ble Authority asked the petitioners to explain

why they could not lower the price and face the competition. Petitioners had pointed out that the landed price of imported tapes is as low as Rs. 3-4 per piece (3 mtr tape). As against this, the stamping fee payable on each tape comes to Rs. 6.25 for 2 mtr.-5mtr. to as high as Rs. 62.50 per piece for 50 mtr tape, leave aside the cost of producing and selling the tapes.

51. The issue at hand being investigated by the Designated Authority is whether the subject goods are being exported to India at dumping prices and whether such imports are causing material injury to the domestic industry.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

52. The Authority examined the issues raised by both the petitioner and M/s. Sudesh Enterprises. The Authority notes that M/s. Sudesh Enterprises did not respond to the questionnaire but made arguments to the preliminary findings, which have been dealt at appropriate places wherever it had a bearing on the findings. As regards the issue raised by M/s Sudesh Enterprises regarding the Non-Injurious price, the Authority notes that the non injurious price is determined after taking into account best consumption norm of raw materials, utilities, SGA and expected profit that an industry is expected to achieve. The anti dumping investigation is basically is to examine the impact of injury caused due to dumped imports by the exporters.

53. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6);

54. Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or

there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

55. The Authority also notes the various custom notification no. 44/99 (NT), dated 15th July 1999, No. 28/2001(NT), dated 31st May 2001 and No. 1/2001(NT), dated 4th January 2002 on the anti dumping in respect of the issue of non market economy under the anti dumping Rules.

56. The Authority provided opportunity to the exporters from subject country to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority also wrote to the Embassy/Representative of subject country in India. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of export price and normal value in accordance with Section 9A(1) (c) of the Custom Tariff Act. The normal value and ex-factory export price determination is examined below.

A. NORMAL VALUE

57. Designated Authority sent questionnaires to the known exporters/producers in China and Embassy of the subject country in India.

58. The Authority notes that none of the exporters from, China PR have responded to the questionnaire sent by the Authority for the purpose of investigation. In view of this non-cooperation, the Authority upholds the claim of the petitioners for treating such producers/exporters on the non-market principle as none of the exporters have rebutted the claim of non- market economy claim by the petitioner. The Authority notes that the petitioner has claimed China PR as a non- market economy on the basis of various findings. The Authority therefore in view of no rebuttal by the exporter on the issue of non market economy and the fact that the cost of production of the subject goods has not been made available by the exporter thus not permitting the authority to apply the ordinary course of trade test, has referenced the normal value separately for both steel tapes and fibre glass tapes on the basis of constructed cost of production with appropriate adjustments on best available information on records as per rule6(8) the anti dumping Rules supra.

59. The Authority has referenced the Normal Value for steel tapes for such producers/exporters as ****\$/Kg and the normal value for fibre glass tapes for such producers/ exporters as ****\$/Kg for the purpose final determination.

B. EXPORT PRICE

60. The Authority notes that the export price has been determined separately for both steel tapes and fibreglass tapes on the basis of the data compiled by DGCI&S Kolkata. Since there is no response from exporters, adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight, and port expenses to an extent of

****\$/Kg, ****\$/Kg, ****\$/Kg, ****\$/Kg. and ****\$/Kg. have respectively considered as provided by the petitioners.

61. The ex-factory export price for steel tapes is referenced as ****\$/Kg and the ex-factory export price for fibreglass tapes is referenced as ****/Kg for the purpose of final determination.

J. DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE:

62. The rules relating to comparison provides as follows:

63. "While arriving at the margin of dumping, the DA shall make a fair comparison between the Export Price and the Normal Value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time.

64. Due allowance shall be made in each case, on merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics and any other differences which are demonstrated to affect price comparability"

65. The Authority has followed the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the Anti Dumping Rules. The authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex-factory export price during Period of Investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporters/producers of the subject country.

The dumping margin for exporter/producers comes as under:

Country	All Exporter/Producer	Normal Value (\$/Kg.)	Ex-Factory export price (\$/Kg.)	Dumping Margin as % of EP
China PR	(Steel Tape)	****	****	1069%
	(Fibre Glass Tape)	****	****	148%

The above Dumping Margins are above the de-minimus limits.

K. INJURY AND CAUSAL LINK:**VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

66. The price at which the domestic industry has exported the material is again irrelevant to determine non-injurious price. Non-injurious price is to be based on cost of production. Selling price cannot become a parameter for non-injurious price. Selling price could be a loss-making price. It is not even the case of the petitioner that its export price is a profitable price. However, should the petitioners reduce their exports, the domestic cost of production would further increase. Petitioners have taken average cost of production, considering the total production, which has been used for determination of non-injurious price.

VIEWS OF SUDESH ENTERPRISES

67. There is a total absence of injury to any of the manufacturers since the quantity and price of the sales has increased substantially during the POI as compared to the previous period. There is absolutely no evidence on record in this regard. For the above reasons, we submit that no duty is liable to be imposed on the imports of measuring tapes from China.

68. In the preliminary findings the duty recommended is the difference between the landed value and US\$ 4.106/Kg. Since the average weight of pocket tapes is around 100 g the unit price would be 0.41 US\$ per piece. After excluding the basic duty and the landing charges, the non-dumped/non injurious import price would about US\$ 0.30. It is submitted that duties are to be levied with regard to lower of the two margins, that is dumping margin or the injury margin. In the present case, FMI Limited has made export at in the months of June and July 2002, to Spain at a unit price of about US\$ 0.21 for 3 Mtrs tapes. The non-injurious price, therefore, cannot be greater than 0.21 US\$, especially since this figure includes overseas freight and insurance. The duty recommended is, therefore excessive and liable to be quashed.

69. In Paragraph 6 of the preliminary findings the Hon'ble Authority has given a finding that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation. In this regard, we submit that there has been no significant decline in the capacity production or domestic sales during the period of investigation as compared to the earlier period. In fact the preliminary findings themselves reveal that the decline, if at all, is less than 2% to 3%. It is admitted that the domestic sales have increased. The claim that the selling price has declined is not factually correct since the petitioner companies have revised their prices upwards on two occasions since 1997 including during the POI by 10% each time. We also find that the petitioner companies are earning over increasing profits, therefore, belying claims that the losses have increased during the period of investigation. In fact, in the case of FMI Ltd., Ferozpur Road, Ludhiana the profit before tax in the year ended 31st March 2000 was 56.32 lacs which increased to 132.82 lacs in the year ended 31st March 2001. This profit remained at its high level during the year ended 31.3.2002 at Rs. 130.10 lacs. Similarly in the case of M/s. Freemans Measure Ltd., Jugiana Road, Ludhiana the profit before tax for the year ended 31st March 2001 was 41.64 lacs, which increased during the period of investigation to 51.23 lacs. Therefore, the claims that the prices have

declined causing the petitioner injury is factually incorrect. The petitioner companies have increased their sales, at profitable level during the POI. The question of inquiry, therefore does not arise.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

70. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

71. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

72. While examination the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 19 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

73. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra."

74. The Authority has taken into account all indices regarding injury while doing the final determination. This would involve all relevant facts viz., volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market and its subsequent effect on domestic producers, production, capacity utilisation, profitability, net sales realisation etc. While determining the non-injurious price for the like article for the domestic industry, the Authority considered the optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and would also take into account the actual price of the raw materials during the period of investigation which go into the production of the product under consideration.

L. MATERIAL INJURY:

75. Following parameters establish that material injury has been caused to the domestic industry from dumped imports from the subject country

Particulars	Unit	1999-00		2000-2001		POI Annualized	
		Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value
Imports							
China	Kg	100283		81228		273906	
Trend		100		81		273	
Other countries	Kg	1021		4790		426	
Trend		100		469		42	
Total imports	Kg	101304		86018		274332	
Trend		100		85		271	
Economic Parameters							
Capacity	KG	989550		989550		989550	
Production		100		95		91	
Capacity Utilization	%	67.89		64.21		61.48	
Domestic sales		100		106		106	
Export Sales		100		72		47	
Total Sales		100	100	96	103	89.86	96.48
Opening Stock	KG	17658.77		24390.95		19500.27	
Trend (Indexed)		100		138		110.43	
Closing Stock	KG	24390.95		19500.27		30159.67	
Trend(Indexed)		100		80		123.65	
Average Stock	Kg	21024.86		21945.61		24829.97	
Trend(Indexed)		100		104		118.10	
Unit Profit/Loss			100		54		-38
Unit cost of production			100		109		110.84
Unit Selling price			100		106		104.79
Return on capital employed	Rs./Lacs		1.72		0.92		0.62
Employment(Indexed)		100		88		81.54	
Salary & Wages(Indexed)		100		109		112.30	
Growth	%			5.36		0.51	
Demand	KG	736076		750190		972951	
Trend(Indexed)		100		102		132	
Imports from China	KG	100283		81228		273906	
Imports from other countries	KG	1021		4790		426	
Total Imports	KG	101304		86018		274332	
Share in Demand							
Domestic Industry	%	65.33		67.73		52.49	
Trend(Indexed)		100		104		80.35	

Other producers	%	20.91	20.80	19.31
Imports from China	%	13.62	10.83	28.15
Trend(Indexed)		100	79	206.64
Imports from other countries	%	0.14	0.64	0.04
Share in Imports				
China	%	99	94	99.84
Trend(Indexed)		100	95	100.86
Other countries	%	1	6	0.16
Imports in relation to production of domestic industry	%	15	14	45.09
Trend(Indexed)		100	90	299.06

Volume and Market share of dumped imports

76. Imports of Measuring Tapes from subject country have increased significantly in (i) absolute terms; (ii) in relation to production; and (iii) in relation to the consumption in India. While the imports are primarily from subject country only, share of imports from China has increased significantly in period of investigation in relation to the demand in India. It is evident from the above that the imports have increased in relation to production of the domestic industry. The Authority also notes that the value of imports have been considered at CIF import price, if the value of imports is compared after including basic import duty, the share would still be higher.

77. The production and capacity utilization of the domestic industry has declined in the period of investigation. This decline in the production and capacity utilization is in spite of the fact that one of the petitioner companies is not very old in terms of commercial production of the subject goods. The rate of growth of imports of subject goods is much more than the rate of growth of domestic production even after demand is showing a increasing trend.

78. Both the petitioner companies determine their prices based on prevailing market conditions. The market prices were driven by the lower prices of the dumped imports as the share of dumped imports has increased from 94% in 2000-01 to 99.94% in 2001-02.

79. Though domestic sales volumes of the domestic industry have marginally increased, the selling price has declined. Further, domestic industry could not reduce its selling price to match dumped imports due to following reasons:-

- a. Measuring Tapes is a consumer product, which is basically sold at retail level. There are hardly any large-scale sales to direct consumers.
- b. The consumers include mainly those people who are not much educated.

c. The landed price of imports is so low compared to the cost of production and selling price of the domestic industry that the domestic industry is not in a position to think of reducing its price to match the price of imported tapes.

d. Considering the situation, the domestic industry had two options, either to match the price or to lose the market. The Authority notes that in this prevailing situation the domestic industry lost both the profit and the market to compete with the dumped imports.

Market share in demand

80. The share of domestic industry in demand has decreased to 52.49% in POI compared to 67.73% in the preceding year. The other producers have also lost their share in demand but by a marginal percentage whereas there is upsurges in imports from China to the extent of 28.15% in POI of the total demand compared to 10.83% in the preceding year. The demand in general has increased from 100 in 1999-2000 to 132 in POI, however, this increase in demand has mostly been occupied by the dumped imports from China. Therefore, the Authority notes that the dumped imports has displaced the market share of domestic industry because of low priced imports of Measuring Tapes from China.

Inventory and evidence of loss of contract

81. The Authority notes that the inventory was decreased from 21024 Kg in 1999-2000 to 19500 Kg in 2000-2001 but it has significantly increased to 32159 Kg in the POI (annualised). The average stock is also showing a increasing trend from 21204 Kg in 1999-2000 to 24829 Kg in the POI (annualised). The Authority holds that the increasing trend in stocks along with the decrease in production in the POI (annualised) is due to the dumped imports from the subject country.

82. It has been claimed that because of the decline in export price, the domestic industry is forced to match the selling price with landed value of exports and the domestic industry is not able to recover even its marginal cost. It is further notice that the domestic industry is unable to sell measuring tapes at such a low price resulting loss of contract. The Authority, therefore, holds that due to the dumped imports, the domestic industry is forced to sell the product at loss.

Price undercutting and Price underselling

83. The Authority notes that in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority considered such further indices having a bearing on the state of industry as production, sales, stock, profitability, net sales realization etc. There are a number of parameters evidencing injury, should the imports be allowed at the present

dumped prices. The rate of increase of imports during the period of investigation from subject country and the corresponding fall in profits of the domestic industry are the parameters clearly in the case the injury is being suffered by the domestic industry. On the basis of the evidence available before the Authority, it is determined that the domestic industry has suffered injury. It has been observed the dumping has had a significant impact on the net sales realisation of the domestic industry for the subject goods. To preserve its market share the petitioner had to compete with low priced and dumped imports of the subject goods from the subject country. The landed price of the dumped imports indicates the evidence of severe price undercutting.

84. The Authority notes that the price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the fair selling price of the product under consideration and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports were having significantly suppressing/depressing effect on the price of the domestic market as the domestic industry is not able to raise its selling price in view of the dumped imports. Thus the examination of the available evidence shows that the domestic industry as a whole suffered injury on its sales of subject goods during POI. The Authority has determined the extent of price undercutting and price underselling during the POI and holds that domestic industry has suffered significant price undercutting and price underselling during the POI due to dumped imports from the subject country.

Employment

85. The employment level of domestic industry has declined during the POI from 100 in 1999-2000 to 88 in 2000-2001 and which is further declined to 81.54 in the POI(annualised). The Authority notes that this change in employment is due to the decrease in production of the subject goods and having a significant loss to the domestic industry.

86. The productivity of the domestic industry has increased due to decline in the number of employees. It is also observed that the production per employee has increased, whereas production per day declined significantly. The Authority, however, notes that this decline in level of employment cannot be ascertained due to the decline in production and capacity utilization.

Profitability

87. The unit cost of production has increased from 100 in 1999-2000 to 110.84 in the annualised POI whereas unit-selling price has also increased from 100 to 104.79 but the unit-selling price has not increased in proportion to the cost of production, which led to the increase in losses. The domestic industry is incurring the loss due to the fact that the domestic industry is forced to reduce the selling price below its cost of production to hold on markets due to dumped imports from subject country. The

industry has suffered the material injury on account of depressed selling price resulting in non-recovery of cost of production thereby suffering financial losses.

88. While cost of sales, production value and sales value have also increased, the increase in the cost of sales is more than increase in the sales value. This has directly resulted in decline in the profits of the domestic industry.

Growth and return in investment

89. The demand for the product has increased however, the growth of the domestic industry has declined significantly. The imports are retarding the growth of the domestic industry in spite of significant demand in the country. It is claimed that due to dumped imports from subject country the domestic industry is doubtful to achieve the target or even to raise capital from the market unless remedial measures is taken to prevent dumped imports from subject country. The Authority notes that it would be difficult for the domestic industry to plan fresh investments.

a) Cash profits of the domestic industry have marginally increased, but return on investment has been further declined in the POI.

b) Wages per employee have increased. However, this increase is more due to the prevailing labour laws in the Country. Further, the increase in the wages has resulted in further increase in the cost of sales, whereas the domestic industry could not maintain its profits.

c) Growth of the domestic industry has declined.

90. The Authority notes that all relevant factors cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered the material injury during the period of investigation due to dumped imports.

M. CAUSAL LINK:

91. In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

92. Substantial imports of subject goods from subject country at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-remunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.

93. The imports from subject country suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

94. The imports from subject country has forced the Domestic Industry to reduce the selling price, which has adversely affected its profitability.

95. The Authority, therefore, notes from the above that the imports from the subject country have been at a price below the selling price of the domestic industry. Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the Domestic Industry. As a consequence, there of, the Domestic Industry has not been able to earn a reasonable return on their investment. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports.

96. The share of volume of dumped imports in total consumption has increased from 10.83% in 2000-01 to 28.15% during POI. The market share of the domestic industry fell from 67.73% in 2000-01 to 52.49% during POI. The dumped imports were coming into India at price that significantly undercut the prices of the like domestic product. The prices of dumped import have caused both price depression and price suppression on the prices of the like domestic products. Thus both volume and price effect is established.

97. There is no contraction in demand (demand has rather increased). Further, there is no other factor such as trade restrictive practice or development in technology which could have material injury to the domestic industry. Increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India have directly resulted increase in the sales, which further resulting in decline in the share of the domestic industry in the demand of the product in the country. Further, the low prices of imports have prevented the domestic industry from optimizing their profitability.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

98. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

99. The Authority also recognises that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

100. The Authority notes that the imposition of anti-dumping measures would also not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

101. The Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioners regarding fair selling price, rather the Authority deputed a team for on-the-spot investigation and verification of costing and manufacturing

process of various forms of measuring tapes, and worked out in detail the fair selling price of measuring tapes in India for the Domestic Industry separately.

O. **CONCLUSIONS:**

102. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Subject goods have been exported to India from subject country below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered material injury;
- (iii) The injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

103. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty on all imports of subject goods from subject country in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the Petitioner Companies determined for the period of investigation.

104. Accordingly, the Authority recommends that the anti dumping duties as set out below be imposed by the Central Government on all imports of subject goods under consideration falling under customs heading 9017, 9017.80, 9017.8001, 9017.90 originating in or exported from subject country. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column no.9 of the following table and the landed value of imports US\$ per Kg. on all imports of subject goods, falling under chapter 48 of the Customs Tariff, originating or exported from the subject territory/country mentioned below:-

TABLE

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring tape	Steel tapes and their parts and components	China,PR	Any Exporter	Any Producer	Any exporter	4.106	Kg.	US\$
2.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring Tape	Steel tapes and their parts and components	Any Country	China,PR	Any producer	Any exporter	4.106	Kg.	US\$
3.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring Tape	Steel tapes and their parts and components	China,PR	China,PR	Any producer	Any exporter	4.106	Kg.	US\$
4.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring Tape	Fiberglass tapes and their parts and components -	Any Country	China,PR	Any producer	Any exporter	4.691	Kg.	US\$
5.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring Tape	Fiberglass tapes and their parts and components -	China,PR	Any Exporter	Any producer	Any exporter	4.691	Kg.	US\$
6.	9017,9017 .80,9017.8 001,9017. 90	Measuring Tape	Fiberglass tapes and their parts and components -	China,PR	China,PR	Any producer	Any exporter	4.691	Kg.	US\$

105. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
106. Subject to the above, the Authority confirms the Preliminary Findings dated 8th January, 2003.
107. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority